

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215174  
SG-DL-E-06012020-215174

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 02, 2020/पौष 12, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 347
No. 02]	DELHI, THURSDAY, JANUARY, 02, 2020/PAUSHA 12, 1941	[N.C.T.D. No. 347

भाग IV  
Part IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

फा. सं. 158 डब्ल्यू.एफ.डी/सी.ओ.टी./17-18/11020-28.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य में द्वारका एक्सप्रेसवे, शिव मूर्ति, NH-8 से सेक्टर- 21 द्वारका, पैकेज -I (कि-मी- 0-000 से कि-मी- 5-300) निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.926 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	
द्वारका एक्सप्रेसवे, शिव मूर्ति, NH-8 से सेक्टर- 21 द्वारका, पैकेज- I	4425	44250 उपभोगी संस्था द्वारा ।
योग	4425	44250

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

1. आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 25,22,25,000 /—रुपये (पच्चीस करोड़ बाईस लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(क)	100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (944 वृक्षों को हटाने तथा 4425 वृक्षों के प्रत्यारोपण के बदले) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अशोक, पीपल, फाइकस, हरड़, बहेड़ा, आमला, शीशम, अर्जुन, अमलतास, आम, सागवान, शहतूत अन्य देशी प्रजातियाँ के साथ तीन स्थानों दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि मौनी बाबा के नजदीक (यमुना नदी), दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि निज़ामुद्दीन से डीएनडी फ्लाईओवर और ग्रीन बेल्ट यूईआर-II उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।	44250	25,22,25,000 /—	उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) / वन अधिकारी

2. देशी प्रजातियों के 44250 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा कराया जायेगा और उनका सात वर्षों तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपरोक्त 1(क) के अनुसार निगरानी की जाएगी।
3. उपभोगी संस्था नए ड्राइंग प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह संकेत दिया जाएगा कि साइट के जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स हैं, जहां वृक्षों का प्रत्यारोपण किया जाएगा और प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
4. 1:10 स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले पौधे 4425 वृक्षों को हटाये जाने के बदले में प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और पश्चिमी वन विभाग द्वारा उपभोगी संस्था द्वारा किए गए जमा का उपयोग करने के बाद रखरखाव किया जाएगा।
5. उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा करेगी। जो कि वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है।
6. उपभोगी संस्था अपने स्वयं के निधियों का उपयोग करके निर्धारित की गई भूमि पर मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को लागू करेगी।
7. उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
8. साइट को अतिक्रमण और बायोटिक हस्तक्षेप से सुरक्षित करना होगा।
9. जहां कहीं भी आवश्यक हो, मृदा तैयार करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप एवं अतिरिक्त बजट उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
10. जिस भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, उसका उपयोग संबंधित वृक्ष अधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
11. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाना चाहिए और इसे 3 महीने के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके बाद एक पूर्ण रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
12. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना अनुमति दी जाएगी, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है।
13. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।

14. वृक्षों को हटाने की अनुमति उपभोगी संस्था को राशि 2,40,00,000/- (दो करोड़ चालीस लाख मात्र) जो कि पैकेज-II, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली में लुप्त 400 वृक्षों के लिए, उप-वन संरक्षक (पश्चिम) दिनांक 09.10.2019 के पत्र में संकेत दिया गया है, को जमा करने के बाद दी जाएगी।
15. 4425 वृक्षों के अतिरिक्त किसी भी वृक्ष की कटाई/प्रत्यारोपण एक अपराध होगा।
16. दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में प्रलेखन का समापन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
17. प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
18. वृक्षों को प्रत्यारोपण/ हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भू-स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी। वृक्षों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।
19. वृक्षों को हटाने/प्रत्यारोपण के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की दुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

### NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2019

**F. No. 158/WFD/ COT/ 17-18/ 11020-28.**—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 27.2951 ha. approx as detailed below for construction of Dwarka Expressway from Shiv Murti, NH-8 to Road Under Bridge near Sector-21, Dwarka (Km. 0.000 to 5.300) Package-I in the State of Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location.	No of trees to be	Compensatory plantation required. (Number of trees)
	Transplanted	
Dwarka Expressway from Shiv Murti, NH-8 to Road Under Bridge near Sector-21, Dwarka (Km. 0.000 to 5.300) Package-I in the State of Delhi	4425	44250 by User Agency.
<b>Total</b>	<b>4425</b>	<b>44250</b>

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. The applicant i.e National Highway Authority of India shall make an advance deposit of an amount of Rs. 25,22,25,000/-(Rupees Twenty Five Crores, Twenty Two Lakh and Twenty Fifth Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the no. of trees permitted for transplant of 4425 (4425 trees i.e 44250 trees for compensatory plantation) trees proposed to be of species Neem, Ashok, Peepal, Ficus, Harad, Bahera, Aamla, Sheesham, Arjun, Amaltas, Aam, Shahtoot along with other native species shall be carried out by User Agency at three locations i.e DDA Land Near Mauni Baba (Yamuna River), DDA Land between Nizamuddin to DND Flyover and Green Belt UER-II.	44250	25,22,25,000/-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

2. 100% Compensatory Plantation of 44250 saplings of native species shall be raised and their maintenance shall be caused by National Highway Authority of India for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) above.
3. The User Agency shall submit fresh drawing indicating the GPS co-ordinates of site where trees would be transplanted and compensatory plantation is proposed to be carried out.
4. 1:10 plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of transplantation of 4425 no. of trees. The plantation shall be done following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance would be carried out there after by West Forest Division utilizing the deposits made by User Agency.
5. User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits)
6. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on identified land division utilizing the deposits made by user agency.
7. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
8. Site shall have to be secured from encroachment and undesired biotic interference.
9. Extensive interventions if any required to be undertaken for soil preparation, would be carried out and additional budget if needed, shall be provided by User Agency.
10. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for any other purpose without the approval of Tree Officer concerned.
11. Transplantation of trees must be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than 3 (three) months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees should not be less than 4 metres (point to point).

12. Permission for felling/ transplantation of trees would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the user agency.
14. Permission of tree removal shall be provided only after the User Agency shall submit the amount Rs. 2,40,00,000 (Two Crores Forty Lakhs only) for the missing 400 Nos. of trees in Package-II, Dwarka Expressway, Delhi as indicated in the letter of DCF (West) dated 09.10.2019.
15. Felling/ Transplantation of any trees apart from 4425 trees by NHAI shall constitute an offence.
16. Completion of documentation regarding compensatory plantation as per provisions of DPTA, 1994 shall be done by User Agency.
17. Progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
18. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned by the user agency. The proceeds shall be deposited as revenue to the Government account. The lops and tops of trees shall be sent/ supplied to nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West)/ Tree Officer.
19. Before shifting of timber if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West).
20. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance if any obtained, must be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the Government  
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)